>

Title: Need to provide ration allowance to non-gazetted police personnel and IRBN personnel of Andaman & Nicobar Islands at par with CRPF and Delhi Police.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदया, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के

नॉन गजेटिड पुलिस पर्सनल्स और इंडिया रिजर्व बटालियंस के करीब 4314 कर्मचारियों के लिए पिछले 22 सालों से हमारा पत्र व्यवहार अंडमान निकोबार प्रशासन और भारत सरकार के साथ चल रहा है। उनकी मांग है कि दिल्ली के पुलिस पर्सनल्स और सीआरपीएफ को जो राशन मनी मिलता है, वह अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस पर्सनल्स और आईआरबीऩ को भी दिया जाए। क्योंकि दिल्ली पुलिस पर्सनल्स की जो बेसिक पे है, उसी आधार पर अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की पुलिस की बेसिक पे निर्धारित हुई है। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की पुलिस या आईआरबीऩ जो काम करते हैं, वह काम हमारी सीआरपीएफ और बार्डर पर तैनात बीएसएफ करता है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की पुलिस और आईआरबीएऩ को जंगल, वन, क्रीक, नाले में फॉरेन नेशनल्स और फॉरेन पोचर्स के साथ मुकाबला करना पड़ता है। उनके ऐसे कठिन काम को देखते हुए उनकी मांग पर 1988 में अंडमान और निकोबार प्रशासन ने भारत सरकार को राशन मनी का प्रपोजल भेजा कि अंडमान और निकोबार के पुलिस पर्सनल्स और आईआरबीएन को भी दिल्ली पुलिस तथा सीआरपीएफ के समान राशन मनी दिया जाए। उसके उपरांत हमारी उम्मीद की किरण जागी। आदरणीय प्रधान मंत्री, डा.मनमोहन सिंह ने 19 जनवरी, 2009 को बारहवीं आइलैंड डैवलपमैन्ट अथारिटी की मीटिंग में जो कहा, वह मैं पढ़कर सुनाता हूं -

"Though Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep are remotely located, they are never far from our thoughts. He further advised that the concerns of the Islands need to be addressed by various Departments of the Government in a sensitive and effective manner."

उसके उपरांत हमारे सम्माननीय उपराज्यपाल महोदय के अनुमोदन से एक पत्र गृह मंत्रालय को दिया गया और यह मांग की गई कि दिल्ली पुलिस पर्सनल्स और सीआरपीएफ को 1992 से 1144 रुपये की दर से प्रतिमाह जो राशन मनी मिल रहा है, उसी के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के नॉन गजेटिड पुलिस पर्सनल्स और आईआरबीएन को भी इसी दर पर प्रतिमाह यह राशन मनी दिया जाए। इस पर भारत सरकार का सालाना कुल 6 करोड़ रुपये खर्च होगा।

मैं पुनः आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह तुंत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के नॉन गजेटिड पुलिस पर्सनल्स और आईआरबीएन के लोगों की इस मांग को पूरा करे। धन्यवाद।

MADAM CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet tomorrow, the 4th March, 2010 at 11 a.m.

18.33 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, March 4, 2010/Phalguna 13, 1931 (Saka).

---

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded as ordered by the Chair.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.